



NEWSMAKERS

भारतीय चीनी उद्योग FRP वृद्धि के अनुरूप एथेनॉल की कीमत में भी चाहता है वृद्धि

नई दिल्ली: चीनी उद्योग सरकार द्वारा हाल ही में घोषित गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) में वृद्धि के अनुरूप एथेनॉल की कीमत में संशोधन की उम्मीद कर रहा है। द हिन्दू बिजनेसलाइन में प्रकाशित खबर के मुताबिक, इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी असोसिएशन (ISMA) के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा कि, पिछले दो वर्षों से एथेनॉल की कीमतों में संशोधन नहीं किया गया है।

बल्लानी ने कहा, पिछले दो वर्षों में, गन्ने के एफआरपी में लगभग 11.5 प्रतिशत का संशोधन हुआ है। हालांकि फीडस्टॉक की कीमतें बढ़ गई हैं क्योंकि यह सरकार द्वारा विनियमित है। एथेनॉल की दर, जिसे सरकार द्वारा भी विनियमित किया जाता है, को संशोधित नहीं किया गया है और इसने वास्तव में हमारी डिस्टिलरी को काफी प्रभावित किया है।

उन्होंने कहा, 2022-23 के दौरान, गन्ने के लिए एफआरपी ₹0 305 प्रति क्विंटल तय किया गया था, जबकि गन्ने के रस से उत्पादित एथेनॉल की कीमत ₹0 65.61 प्रति लीटर तय की गई थी। बी-हैवी मोलासेस से उत्पादित एथेनॉल के लिए, वर्ष के दौरान कीमत ₹0 60.73 प्रति लीटर और सी-हैवी मोलासेस के लिए, यह ₹0 49.41 प्रति लीटर तय की गई थी। 2023-24 के दौरान एफआरपी को बढ़ाकर ₹0 315 प्रति क्विंटल और फिर चालू 2024-25 चीनी सीजन के दौरान ₹0 340 प्रति क्विंटल कर दिया गया।

मक्के से उत्पादित एथेनॉल से भी कम कीमत...

जबकि सरकार मक्के से उत्पादित एथेनॉल के लिए ₹0 72 प्रति लीटर दे रही है, वहीं गन्ने से एथेनॉल केवल ₹0 65.61 मिल रहा है, जो उत्पादन लागत से काफी कम है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि पूरे एथेनॉल मूल्य निर्धारण में यह एक बड़ी विसंगति है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से, जब भी एफआरपी में वृद्धि हुई है, सरकार ने एथेनॉल की कीमत बढ़ा दी है या सही किया है। यह लगभग पांच वर्षों तक किया गया था, लेकिन पिछले दो वर्षों में इसमें संशोधन नहीं किया गया।

बल्लानी ने कहा, क्योंकि सरकार ने एथेनॉल के लिए उचित मूल्य प्रशासनिक तंत्र का आश्वासन दिया है, उद्योग ने लगभग ₹0 40,000 करोड़ के निवेश के साथ एक बड़ी क्षमता स्थापित की है। आज हमारे पास करीब 850 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन क्षमता है। कीमतों में सुधार नहीं होने से कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। अब एफआरपी को 2025-26 के लिए फिर से बढ़ाकर 355 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। अब हमें उम्मीद है कि, सरकार एथेनॉल की कीमत जरूर बढ़ाएगी या उसमें सुधार करेगी। अन्यथा एथेनॉल में पूरा बदलाव एक बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा।

उन्होंने कहा, हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि यह तीसरा साल होगा जब कीमतों में सुधार नहीं किया गया है। इसलिए एफआरपी से एथेनॉल की कीमत में लिंकेज

फार्मूले के अनुसार कीमतें तय की जानी चाहिए। और टेंडर जारी होने से पहले इस पर फैसला और घोषणा की जानी चाहिए। इसके अलावा, बल्लानी ने कहा कि 315 रुपये प्रति क्विंटल के गन्ने के एफआरपी के लिए, उद्योग सूत्र के अनुसार, गन्ने के रस से उत्पादित एथेनॉल के लिए 71 रुपये प्रति लीटर, बी-हैवी मोलासेस के लिए लगभग 65 रुपये और सी-हैवी मोलासेस के लिए 61 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर विचार कर रहा था। उन्होंने कहा, 340 रुपये के एफआरपी के लिए, सिरप से उत्पादित एथेनॉल की कीमत 73.14 रुपये प्रति लीटर, बी-हैवी मोलासेस के लिए 67.70 रुपये और सी-हैवी मोलासेस के लिए 61.20 रुपये प्रति लीटर होती। सूत्र के अनुसार, 355 रुपये प्रति क्विंटल पर एथेनॉल की कीमत अब स्पष्ट रूप से बढ़ जाएगी।

Source: Chinimandi, 22nd May, 2025

उत्तर प्रदेश: GSVA में गन्ने का योगदान 19.4% रहा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के जिला घरेलू उत्पाद पर 2023-24 के लिए हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, प्राथमिक क्षेत्र, खासकर कृषि ने राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी के 25.63 लाख करोड़ रुपये के जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 6.35 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से 3.96 लाख करोड़ रुपये का योगदान सिर्फ फसल क्षेत्र का है। यूपी सरकार के नियोजन विभाग के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी प्रभाग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023-24 में राज्य की अर्थव्यवस्था में फसलों का योगदान 16.8% था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.74% की वृद्धि दर्ज करता है।

प्रमुख सचिव, नियोजन, आलोक कुमार ने कहा, यूपी लगातार खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर रहा और राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं और गन्ना उत्पादन में अग्रणी स्थान बनाए रखा। 2023-24 में, राज्य ने 6.68 करोड़ टन खाद्यान्न और 3.98 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन किया, जो भारत के कुल खाद्यान्न और गेहूं उत्पादन में क्रमशः 18.14% और 31.19% का योगदान देता है। 2023-24 में, यूपी ने 2,495 लाख टन गन्ने का उत्पादन किया। रिपोर्ट बताती है कि, राज्य सरकार के हस्तक्षेप से समय पर भुगतान और कुशल पेराई के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास में मदद मिली है। गन्ना उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देने वाले शीर्ष पांच जिले लखीमपुर खीरी (3.22 करोड़ टन), बिजनौर (2.37 करोड़ टन), सीतापुर (1.9 करोड़ टन), मुजफ्फरनगर (1.68 करोड़ टन) और मेरठ (1.46 करोड़ टन) हैं। गन्ना उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि वाले जिले आजमगढ़ (53.5%), मऊ (49.6%), जौनपुर (33.7%), रायबरेली (24.7%) और मथुरा (21%) थे।

फसलों की मात्रा के मामले में शीर्ष पांच जिलों में लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, बिजनौर और बदायूं शामिल हैं। इसी तरह, फसलों में सबसे अधिक वृद्धि



UPSMA
UP SUGAR MILLS ASSOCIATION

वार्ता The Dialogue

JUNE, 2025

Monthly Newsletter of UPSMA

VOL: III, ISSUE: 309

वाले शीर्ष पांच जिले भदोही, जालौन, कानपुर देहात, रायबरेली और झांसी थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि, कम से कम 37 जिलों ने राज्य के औसत 13.7% से अधिक वृद्धि दर दर्ज की है। प्रमुख सचिव, नियोजन, आलोक कुमार ने कहा कि आंकड़ों के अनुसार, फसल क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धित (GSVA) मुख्य रूप से खाद्यान्न द्वारा संचालित था, जिसने जीएसवीए में 40.68% का योगदान दिया। फलों और सब्जियों का योगदान GSVA में 22.58% और गन्ने का योगदान 19.4% रहा। यूपी लगातार खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना रहा और राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं और गन्ना उत्पादन में लगातार अग्रणी स्थान बनाए रखा। कुमार ने कहा, 2023-24 में, राज्य ने 6.68 करोड़ टन खाद्यान्न और 3.98 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन किया, जो भारत के कुल खाद्यान्न और गेहूं उत्पादन में क्रमशः 18.14% और 31.19% का योगदान देता है।

राज्य ने 2.65 करोड़ टन की उपज के साथ भारत के कुल धान उत्पादन में 11.6% का योगदान दिया। धान क्षेत्र को जल संरक्षण योजनाओं से लाभ हुआ, बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे क्षेत्रों में उत्पादन में क्रमशः 2.09% और 7.89% की वृद्धि दर्ज की गई। खेत तालाब योजना और अमृत सरोवर जैसी पहलों ने भूजल स्तर में सुधार किया, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि हुई। यूपी के विभिन्न कृषि उत्पाद भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, प्रतापगढ़ का आंवला, मलीहाबाद का दशहरी आम और चंदौली का आदमचीनी चावल इसके कुछ उदाहरण हैं। 2023-24 में आम का निर्यात 567.62 टन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.59% की वृद्धि है। आम उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देने वाले शीर्ष पांच जिले उन्नाव, लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ और सीतापुर हैं। आम उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि वाले पांच जिले चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, बांदा और ललितपुर हैं।

Source: Chinimandi, 29th May, 2025

नया शोध: चीनी मिलें राख से बना सकती हैं ईट, महाराष्ट्र और यूपी के चीनी मिलों में इस तकनीक का इस्तेमाल शुरू

कानपुर : चीनी मिलों के राजस्व में बढ़ोतरी करनेवाला नया विकल्प खुल गया है, जो पर्यावरण अनुकूल भी है। 'जनता से रिश्ता' में प्रकाशित खबर के मुताबिक, चीनी मिलों से निकलने वाली राख वायु प्रदूषण का बड़ा कारण है, लेकिन अब इसका पर्यावरण अनुकूल और स्थायी समाधान मिल गया है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के पूर्व निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन के नेतृत्व में शोध दल ने इससे टिकाऊ ईट तैयार करने की विधि विकसित की है।

महाराष्ट्र के कोल्हापुर और यूपी के सीतापुर के रामगढ़ की चीनी मिलों में भी इस तकनीक का इस्तेमाल शुरू हो गया है। अब दोनों चीनी मिलों की राख से ईटें बनाई जा



रही हैं, जो परंपरागत ईटों से ज्यादा मजबूत और नमी रहित हैं। इन ईटों से बनी दीवारों पर प्लास्टर करने की जरूरत नहीं है। पांच हजार टन गन्ना पेराई करने वाली एक चीनी मिल से प्रतिदिन 20 टन तक राख निकलती है। अभी तक चीनी मिलों द्वारा इस राख का निपटान गड्ढों को भरकर किया जाता रहा है, लेकिन चीनी मिलों से निकलने वाली राख में कई तरह के रसायन होने के कारण इसे मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। लेकिन अब टिकाऊ ईट बनाने के इस नए शोध के चलते प्रदूषण भी नहीं होगा उअर मिलों का राजस्व भी बढ़ सकता है।

Source: Chinimandi, 4th June, 2025

रिकॉर्ड गन्ना पेराई कर, खतौली मिल बनी देश में प्रथम

चीनी उत्पादन में त्रिवेणी समूह की चीनी मिल खतौली ने पेराई सत्र 2024-25 में देश में सर्वाधिक गन्ना पेराई का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। खतौली चीनी मिल द्वारा वर्तमान पेराई सत्र में देश में सर्वाधिक गन्ना पेराई का रिकॉर्ड अपने नाम किया गया है। चीनी मिल ने अपने स्थापनाकाल से सबसे अधिक गन्ना पेराई के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 2.51 करोड़ कुंतल गन्ना पेराई करके नया कीर्तिमान बनाया है। चीनी मिल में 25 अक्टूबर 2024 में पेराई सत्र शुरू हुआ जो 196 दिनों तक चला।

पूरे देश में वर्तमान में 525 चीनी मिल हैं। 2024-25 के पेराई सत्र में इनमें से 472 चीनी मिलों में पेराई हुई। प्रतिदिन 1.6 लाख कुंतल गन्ने की पेराई करने वाली खतौली चीनी मिल इन सभी 472 चीनी मिलों को पछाड़ दिया और नंबर एक पर पहुंच गई। इस साल इस चीनी मिल ने 250.12 लाख कुंतल गन्ने की पेराई की है। मिल प्रबंधन का कहना है कि खतौली चीनी मिल ने 1933 में स्थापित होने के बाद से अब तक सबसे अधिक गन्ना पेराई की है।

यूनिट हेड डॉ. अशोक कुमार ने कहा कि चीनी मिल द्वारा 251 लाख कुंतल गन्ना पेराई करके नया कीर्तिमान बनाना और पेराई जारी रहने के लिए क्षेत्रीय किसानों के परिश्रम और सहयोग, जिला गन्ना अधिकारी, उप गन्ना आयुक्त और मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के कुशल निर्देशन से ही संभव हो पाया है, जिसके लिए उन्होंने सभी चीनी मिल अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि चीनी मिल द्वारा देश में सर्वाधिक गन्ना पेराई करने में चीनी मिल के अधिकारियों, कर्मचारियों का परिश्रम और सहयोग भी अत्यंत सराहनीय रहा है।

Source: Sugar Times, May, 2025

BCML LAUNCHES 'BALRAMPUR BIOYUG', INDIA'S FIRST INDUSTRIAL-SCALE PLA BIOPOLYMER BRAND

Balrampur Chini Mills unveils India's first industrial-scale PLA biopolymer brand 'Bioyug', marking a transformative step towards sustainable and circular economy solutions.

Mumbai, May 27, 2025 – Balrampur Chini Mills Limited (BCML) officially launched 'Balrampur Bioyug', India's first industrial-scale PLA (Polylactic Acid) biopolymer brand, at a high-profile

Continued on the next page ...



UPSMA
UP SUGAR MILLS ASSOCIATION

वादा The Dialogue

JUNE, 2025

Monthly Newsletter of UPSMA

VOL: III, ISSUE: 309

event held at Jio World Convention Centre, Mumbai. The brand launch was graced by Hon'ble Maharashtra Chief Minister Shri Devendra Fadnavis, marking a milestone in India's green manufacturing journey.



India's First Industrial-Scale PLA Brand to Be Produced in Uttar Pradesh

Balrampur Bioyug will be produced at a state-of-the-art facility currently under development in Kumbhi, Uttar Pradesh, adjacent to BCML's existing sugar complex. With a significant investment of ₹2,850 crores, the upcoming plant will convert sugarcane into PLA using 100% renewable energy.

Once operational, the facility is projected to produce up to 80,000 tonnes of bio-based, industrially compostable PLA annually—offering a scalable, eco-friendly alternative to petroleum-based plastics.

'Bioyug on Wheels': Sustainability on the Move

The event also featured the unveiling of 'Bioyug on Wheels' — a mobile experience center that brings the story and uses of PLA directly to people.

Featuring interactive exhibits, live demonstrations, and product showcases, the initiative aims to raise awareness about bioplastics and foster mainstream adoption.

Balrampur Bioyug promises to reduce CO₂ emissions by 68% over the lifecycle compared to traditional plastics, offering a credible, scalable solution to India's single-use plastic challenge — and advancing the circular economy mission.

Source: Sugar Times, 27th May, 2025

23 LMT MONTHLY SUGAR QUOTA RELEASED FOR JUNE 2025; JUNE 2024 CONSUMPTION WAS 24.10 LMT

In an announcement on May 28, the Food Ministry allocated a monthly sugar quota of 23 lakh metric tonnes (LMT) for June 2025, which is lower than the quota allocated for June 2024.

and was 25.50 LMT. Allocated quota for June 2025 to UP is 9.48 LMT as against 9.27 LMT for May 2025.

According to market experts, with the announcement of 23 LMT, the market sentiments are expected to remain bearish. Last year, in June, sugar consumption was 24.10 LMT

Source: Chinimandi, 28th May, 2025

UTTAR PRADESH TO LAUNCH FIRST-OF-ITS-KIND SAF POLICY; 18 COMPANIES EXPRESS INTEREST IN INVESTING IN SECTOR

Lucknow: The Uttar Pradesh government is set to introduce the Uttar Pradesh Sustainable Aviation Fuel (SAF) Manufacturing Promotion Policy-2025, which officials say will be the first policy of its kind in the country.

Chief Secretary Manoj Kumar Singh on Sunday briefed industry leaders and investors about the policy during an event organized by Invest UP.

The event began with a comprehensive presentation by Invest UP officials, highlighting the state's vision to position Uttar Pradesh as a hub for SAF manufacturing. Designed as a collaborative forum, the roundtable invited industry established industry players and potential investors to share insights and suggestions to help shape a robust and investment-ready policy.

Singh highlighted several features of the policy, including incentives for businesses, streamlined support from the government, and the state's advantages as a production hub. He pointed out that the policy also has the potential to significantly benefit farmers in the state.

Singh stated that the SAF industry's need for biomass and grain-based feedstock—such as sugarcane bagasse, rice husk, wheat straw, and surplus grains—will open up new market opportunities for farmers.

"This policy not only supports our shift to clean energy, but also makes sure our farmers benefit directly by increasing their income and contributing to a greener future," Singh said.



Continued on the next page ...



UPSMA
UP SUGAR MILLS ASSOCIATION

वार्ता The Dialogue

JUNE, 2025

Monthly Newsletter of UPSMA

VOL: III, ISSUE: 309

The event included a detailed presentation on the SAF vision for the state, followed by discussions with industry representatives. Topics such as land availability, policy framework, and ease of doing business were addressed.

More than 18 companies, including prominent names like Greenko, New Era Clean Tech Solutions, and Oasis Group (Malbros Group), have expressed strong interest in investing in the SAF sector in Uttar Pradesh. Investment intents exceeding Rs. 3,000 crore have been received, reflecting significant industry confidence in the initiative.

The investors provided constructive inputs on the policy framework, land allotment processes, proposed incentive mechanisms and also shared their wishlist for the government.

Singh also emphasized the state's strong infrastructure network, which includes five international airports and extensive air, rail, and road connectivity, making it an ideal location for SAF production and distribution.

Earlier, Invest UP issued an Expression of Interest (EOI) to invite global technology providers and innovators in the clean energy sector to become part of the initiative.

Invest UP CEO Vijay Kiran Anand and senior officials from various departments were present at the event.

Source: Chinimaandi, 02nd June, 2025

UTTAR PRADESH: ETHANOL PLANT INAUGURATED IN CHHATA; UNIT TO USE STUBBLE FOR IN-HOUSE POWER GENERATION

The ethanol unit of Allianz Distillery Limited, located in Chhata, was inaugurated by the Minister of sugar mill and sugarcane development, Laxmi Narayan Chaudhary, along with a representative of the company.



This is a 100 KLPD (Kiloliters Per Day) grain-based ethanol plant, established with an investment of Rs 160 crore.

The plant will procure crop residues such as stubble from farmers and utilize them for power generation.

While speaking to ChiniMandi, Company director Sanjay Sangwan stated that the ethanol produced at the plant will be blended with petrol. The plant is fully equipped with the necessary infrastructure, including an in-house power plant. Stubble will be used for electricity generation.

The director further mentioned that their aim is to procure maize and rice from farmers at fair prices. Minister Chaudhary Laxmi Narayan praised the company's initiative, calling it highly commendable.

The use of stubble for electricity generation will significantly benefit farmers. The ethanol unit is also expected to generate employment for local youth.

Source: Chinimaandi, 10th June, 2025

Knowledge Box

During Pre-Independence Era

Sr No	Item	Cost	
		annas	pies
1	Actual cost of cultivation	4	6
2	Interest on working capital	0	3
3	Insurance against damages	0	9
4	Cartage	1	6
5	Profit	1	0
6	Total	8	0

UPSMA Newsletter titled 'Varta' the Dialogue is providing information on sugar, sugar industry and sugar byproducts. We request you to share your thoughts and experience with us through write-ups, success stories, updates, photographs etc. We publish your creative in the next edition of this newsletter. You are requested to send your entries to be published in UPSMA newsletter through mail at upsma@upsma.org. The newsletter will be uploaded on UPSMA website.

अस्वीकरण: यहाँ दी गई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा या अन्य स्रोतों से ली गई है, जिन्हें विश्वसनीय माना जाता है और इस पर इस तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इस समाचार में दी गई जानकारी में किसी भी अनजाने त्रुटि से किसी भी व्यक्ति को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए 'वार्ता टीम' किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगी। इस दस्तावेज़ में दी गई जानकारी इस समाचार की तारीख तक है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य के परिणाम या घटनाएँ इस जानकारी के अनुरूप होंगी।